भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

तारांकित प्रश्न सं. *342

(जिसका उत्तर सोमवार 18 अगस्त, 2025 /27 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

आर्थिक अस्थिरता

***342. श्री जिया उर रहमान:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बढ़ते राजकोषीय घाटे, बढ़ती मुद्रास्फीति और भू-राजनीतिक तनाव तथा आपूर्ति शृंखला में व्यवधान जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक अस्थिरता के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री

(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री ज़िया उर रहमान द्वारा आर्थिक अस्थिरता पर दिनांक 18 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए पूछा गया लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *342 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): अभूतपूर्व भू-राजनीतिक अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों और अस्थिर वैश्विक विकास की संभावना के होते हुए भी, भारतीय अर्थव्यवस्था ने विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक प्रबंधन, विश्वसनीय राजकोषीय समेकन, बाहरी सैक्टर का मजबूत प्रदर्शन और स्थायी संरचनात्मक सुधारों के आधार पर अपना सामर्थ्य दिखाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 प्रतिशत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर्ज करने के साथ, भारत तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 9.2 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.8 प्रतिशत हो गया है, और वित्त वर्ष 2025-26 में इसे और घटाकर सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत करने की योजना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जरिए मापी गई औसत खुदरा मुद्रास्फीति दर पिछले छह वर्षों में सबसे कम, वित्त वर्ष 2024-25 में 4.6 प्रतिशत रही जो अप्रैल-जुलाई 2025 में और कम होकर 2.4 प्रतिशत हो गई है। अस्थिर वैश्विक व्यापार के बावजूद, भारत के निर्यात प्रदर्शन ने समुत्थानशीलता को साबित किया है, और देश का समग्र निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में 824.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया है। यह सकारात्मक रुझान चालू वित्त वर्ष में भी जारी रहा है और पहली तिमाही के दौरान समग्र निर्यात में 5.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने से अधिक के माल आयात के लिए पर्याप्त है। यह निरंतर व्यापक आर्थिक प्रदर्शन, भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक और आर्थिक अनिश्चितताओं से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता को स्पष्ट करता है।

(ख) और (ग): सरकार ने व्यापक और समावेशी आर्थिक विकास की गति को बनाए रखते हुए, समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक अस्थिरता के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के उद्देश्य से ठोस उपाय किए हैं। बुनियादी जरूरतों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, आजीविका के अवसरों को बढ़ाने और कमज़ोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी प्रमुख योजनाओं को लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास, उद्यमिता प्रोत्साहन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पहलें इन प्रयासों को और मज़बूत बनाती हैं। इसके साथ-साथ, सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापक उपाय किए हैं, जिनमें बढ़ा हुआ पूँजीगत व्यय, अवसंरचना का विकास, वित्तीय क्षेत्र में सुधार और व्यापार करने में सुगमता में सुधार के लिए पहलें शामिल हैं।

***